CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

घसियारी कल्याण योजना का उद्घाटन करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह

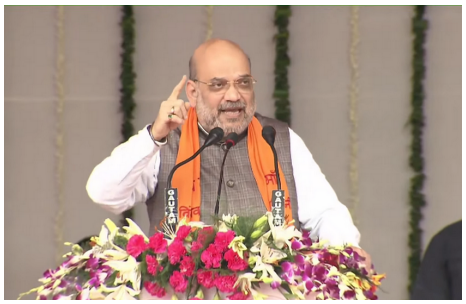

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अक्टूबर के आखिरी दिनों में देहरादून में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना (MGKY) का उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में यह योजना चार पर्वतीय जिलों पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत में शुरू की जाएगी।
- योजना के तहत सहकारी समितियों के सहयोग से पशुपालकों को पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि पशुपालकों को 25-30 किलोग्राम के वैक्यूम पैक बैग में पशु चारा (सिलेज) रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। सिलेज हरे चारे, मक्का और सूखे चारे का उपयोग करके तैयार किया गया है।
- मंत्री ने कहा कि फ़ीड से मवेशियों के दूध उत्पादन में 15 से 20 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मध्य प्रदेश में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का उपयोग कर पैदा हुई दो मादा बछड़े

- नाना जी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश के शोधकर्ताओं ने भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक की मदद से दो मादा बछड़ों को सफलतापूर्वक पैदा किया है।
- भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक में बेहतर नस्ल के मवेशियों के भ्रूण और वीर्य का उपयोग करके गायों को प्रजनन करना शामिल है, जिसे बाद में कम उत्पादक गायों में प्रत्यारोपित किया जाता है।
- माना जा रहा है कि यह तकनीक भारत में पशुपालन में क्रांति लाएगी। "यह हमारे राज्यपाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसे संस्थान ने हाथ में लिया है। हम गौशाला से कुछ बीमार गायों को लाए और साहीवाल गाय के जीन प्लाज्म का उपयोग करके भ्रूण प्रत्यारोपण किया। नतीजतन, आज दो बछड़ों का जन्म हुआ, "विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी मिश्रा ने कहा।

गोवा की डेयरी फार्मिंग किट योजना को बढ़ाया जाएगा

- गोवा में आदिवासी और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए योजना, जो समुदायों को पशुपालन गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक डेयरी किट प्रदान करती है, किट में और अधिक मदों को जोड़कर बढ़ाया जा रहा है।
- इस संबंध में एक फाइल पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय (एएचवीएस) द्वारा सरकार को भेजी गई है और अनुमोदन के लिए लंबित है।
- "योजना का पुराना संस्करण आदिवासी समुदाय से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण, हमने अब इस योजना को बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि समुदाय के सदस्य आगे आएं और डेयरी किट सब्सिडी का लाभ उठाएं। संशोधन के बाद यह योजना किसानों के लिए लाभदायक होगी। एएचवीएस के एक अधिकारी ने कहा।
- वस्तुओं का कुल मूल्य जो पहले 5,000 रुपये से अधिक नहीं था, अब 30,000 रुपये की सीमा होगी। इस योजना में समुदाय को 100% सब्सिडी मिलेगी।

CEDSI डेयरी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों के पैनल के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। पृष्ठ 5-7 पर विस्तृत विज्ञापन पढ़ें।

गुजरात में पैदा हुआ भारत का पहला आईवीएफ भैंस बछड़ा

- भारत में पहली बार, इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) तकनीक का उपयोग करते हुए, गुजरात के सोमनाथ जिले के एक निजी खेत में 'बन्नी' नाम की नस्ल की भैंस के बछड़े का जन्म हुआ।
- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि देश का पहला आईवीएफ भैंस का बछड़ा छह बन्नी आईवीएफ गर्भधारण से पैदा हुआ था, जो किसान के घर पर स्थापित किया गया था।
- मंत्रालय कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशुधन प्रजनन के लिए एक योजना चलाता है जैसे कि आईवीएफ के माध्यम से जहां एक प्रशिक्षित तकनीशियन भैंस पर तकनीक का प्रदर्शन करता है।
- कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान (AITI) देश भर में राज्य सरकार, सहकारी समितियों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गैर सरकारी संगठनों और निजी एजेंसियों की छत्रछाया में संचालित होते हैं।
- राष्ट्रीय पशुधन नीति उन्नत कृत्रिम गर्भाधान कवरेज के माध्यम से पशुधन की उत्पादकता में सुधार, प्रजनन के लिए उच्च आनुवंशिक योग्यता रोग-मुक्त उपलब्धता में सुधार और पशुधन उत्पादन का समर्थन करने वाले बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने पर विशेष जोर देती है।

लंपी स्किन डिजीज : बीमारी पर शोध के लिए पशुओं का एकत्र होगा ब्लड सीरम

संतकबीरनगर जिले में पशुओं में एक नई बीमारी तेजी से फैल रही है। इसे लंपी स्कीन डिजीज के नाम से जाना जाता है। वायरस जनित बीमारी होने की वजह से इसका अभी तक कोई कारगर इलाज नहीं ढूंढ़ा जा सका है। अब बीमार पशुओं का ब्लड सीरम संकलित किया जाएगा। हर माह संक्रमित पशुओं का ब्लड सैंपल भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र बरेली में भेजा जाएगा। इसके लिए जिला स्तर पर व्यापक तैयारी कर ली गई है। ताकि यह पता चल सके कि जानवरों में यह बीमारी कैसे फैल रही है, इस पर और शोध हो सके। बीमारी होने पर पशुओं में जिस प्रकार का लक्षण नजर आता है उसी अनुरूप दवाएं दी जाती हैं। जिले में दो दर्जन से अधिक गाय और भैंस इस बीमारी के चपेट में आ चुके हैं। नाथनगर और कालीजगदीशपुर में इस प्रकार के बीमारी के लक्षण नजर आए हैं। इसके अलावा मेंहदावल और बखिरा क्षेत्र में भी इस बीमारी से ग्रसित जानवर देखे गए हैं।

बीमारी के लक्षण

लंपी स्किन डिजीज में जानवर के शीरर पर गाठें बन जाती हैं। बाद में यही गाठ फूट कर फोड़े में तब्दील हो जाती है। पैरों में सूजन और घाव हो जाता है। जानवर भोजन करना बंद कर देता है। अत्यधिक बुखार होने के साथ साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं। बीमारी भयावह होने पर गर्भवती गाय और भैंस का गर्भपात होने की आशंका बनी रहती है। यदि जानवर की समय से देखभाल न की जाए तो उसकी मौत भी जाती है।

संक्रमित पशु को रखें दूर

इस बीमारी के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। इसलिए जैसे ही इस बारे में पता चले वैसे ही संक्रमित पशु को अन्य जानवरों से अलग कर दें। हो सकता है कि यह बीमारी जानवर से मनुष्य में फैल जाए। इसलिए ग्लब्स पहन कर ही पशुओं को चारा खिलाएं। बेहतर होगा कि इस पशु की देखभाल करने वाला व्यक्ति परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहे। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. ओपी मिश्र ने बताया कि इस बीमारी के लिए पाक्स वायरस जिम्मेदार है।

डेयरी-टेक फर्म स्टेलैप्स ने $18 मिलियन जुटाए

डेयरी सप्लाई चेन में काम करने वाली इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) फर्म, स्टेलैप्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड ने कहा कि उसने डच पशु पोषण और जलीय कृषि कंपनी न्यूट्रेको के नेतृत्व में सीरीज सी फंडिंग राउंड में 1.8 करोड़ डॉलर जुटाए हैं।

स्टेलैप्स एक डेयरी डिजिटलीकरण सेवा प्रदाता है जो डेयरी उद्योग में ग्राहकों को उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ आपूर्ति श्रृंखला में ट्रेसबिलिटी प्रदान करने में मदद करता है। स्टार्टअप ने अपने ट्रैसेबिलिटी नेटवर्क को बढ़ाने और अपने डिजिटल फुटप्रिंट का विस्तार करने के लिए धन का उपयोग करने की योजना बनाई है।

"हम अपने स्मार्टमू समाधानों के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने, गुणवत्ता में सुधार और ट्रेसबिलिटी को सक्षम करके भारतीय छोटे किसानों को कृषि उद्यमी कक्षा में स्थानांतरित करने के मिशन पर हैं। हमारे निवेशकों का समर्थन और विश्वास हमें हमारे प्रौद्योगिकी समाधानों, कृषि आदानों और बाजार संबंधों के संयोजन के माध्यम से किसानों की आय और लाभप्रदता बढ़ाने के हमारे दृष्टिकोण को साकार करने की अनुमति देता है," स्टेलैप्स के सीईओ रंजीत मुकुंदन ने कहा।

रिलायंस रिटेल ने मिल्कबास्केट का अधिग्रहण पूरा किया, 96.49% हिस्सेदारी हासिल की

उपभोक्ता इंटरनेट स्टार्टअप्स के अधिग्रहण की होड़ को जारी रखते हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने मिल्कबास्केट के अधिग्रहण की पुष्टि की है। कंपनी ने Q2 FY22 वित्तीय परिणामों की घोषणा के दौरान इसका खुलासा किया। लेन-देन के वित्तीय विवरण का खुलासा किए बिना, समूह ने कहा, "आरआरवीएल ने तिमाही के दौरान एआईडिया सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (मिल्कबास्केट) में 96.49% हिस्सेदारी हासिल की।"

अगस्त में, रिलायंस रिटेल के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) निखिल के चक्रपाणि और रिलायंस कंटेंट मैनेजमेंट के सीएफओ राजेंद्र कामथ, अतिरिक्त निदेशक के रूप में मिल्कबास्केट के निदेशक मंडल में शामिल हुए। मिल्कबास्केट निवेश के लिए बिगबास्केट, अमेज़ॅन, स्विगी और अन्य के साथ भी बातचीत कर रही थी।

अनंत गोयल, आशीष गोयल, अनुराग जैन और यतीश तलवाडिया द्वारा 2015 में स्थापित, मिल्कबास्केट फलों और सब्जियों, डेयरी, बेकरी और अन्य में घरेलू किराने की जरूरतों को पूरा करता है। अधिग्रहण से पहले, स्टार्टअप ने 11 फंडिंग राउंड में 38.5 मिलियन डॉलर जुटाए थे।
स्टार्टअप जो 130K घरों को वितरित करने और सब्जी, डेयरी, बेकरी, फलों सहित 9,000 उत्पादों की पेशकश करने का दावा करता है, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद और बेंगलुरु में चालू है।

मिल्मा केंद्रीय संघ डेयरी किसानों की मदद करेगा

एर्नाकुलम क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ जिसमें त्रिशूर, एर्नाकुलम, कोट्टायम और इडुक्की जिले शामिल हैं, ने इन जिलों के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित डेयरी किसानों और प्राथमिक दूध सहकारी समितियों को मदद करने का फैसला किया है।

मिल्मा एर्नाकुलम क्षेत्र के अध्यक्ष जॉन थेरुवथ ने कहा कि संघ ने इस सप्ताह की शुरुआत में बारिश से संबंधित आपदाओं में अपनी जान गंवाने वाले डेयरी किसानों के प्रत्येक परिवार को 25,000 रुपये का अनुग्रह भुगतान देने का फैसला किया है। जिन किसानों की गायों का बीमा नहीं हुआ है, उन्हें 20000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। जिन लोगों के गौशाला बारिश और हवाओं में क्षतिग्रस्त हो गए थे, उन्हें 20000 रुपये मिलेंगे। जिन किसानों के पशु चारा और स्वचालित दूध संग्रह इकाइयों को नुकसान हुआ है, उन्हें प्रत्येक को 10000 रुपये मिलेंगे।

एशियाई विकास बैंक महाराष्ट्र में कृषि व्यवसाय विकास के लिए $100 मिलियन का ऋण प्रदान करेगा

- एशियाई विकास बैंक महाराष्ट्र में कृषि आय को बढ़ावा देने और खाद्य नुकसान को कम करने के लिए कृषि व्यवसाय नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए 100 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 749 करोड़ रुपये) का ऋण प्रदान करेगा।
- एडीबी अपने तकनीकी सहायता विशेष कोष से 500,000 अमेरिकी डॉलर की तकनीकी सहायता (टीए) अनुदान और एफपीओ के लिए बाजार संबंधों में सुधार के लिए अनुदान के आधार पर जापान फंड से गरीबी में कमी के लिए 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान भी प्रदान करेगा।
- महाराष्ट्र एग्रीबिजनेस नेटवर्क (मैग्नेट) परियोजना के लिए समझौते पर भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर ताकेओ कोनिशी के बीच हस्ताक्षर किए गए।
- वित्त मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि एडीबी ऋण किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और मूल्य श्रृंखला ऑपरेटरों (वीसीओ) के लिए 300 उप-परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए अनुदान और वित्तीय मध्यस्थता ऋण के माध्यम से वित्तपोषण के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।
- यह परियोजना 16 मौजूदा फसल कटाई के बाद की सुविधाओं को अपग्रेड करेगी और व्यक्तिगत किसानों और एफपीओ को स्वच्छ, सुलभ और टिकाऊ फसल भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 3 नए का निर्माण करेगी।
- यह मूल्य श्रृंखला त्वरण और कटाई के बाद प्रबंधन और प्रबंधन पर एफपीओ और वीसीओ की क्षमता का निर्माण भी करेगा, विशेष रूप से महिलाओं के स्वामित्व और नेतृत्व वाले। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस परियोजना से 200,000 किसानों को लाभ होने की उम्मीद है।

CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

AN INITIATIVE OF AGRICULTURE SKILL COUNCIL OF INDIA

CEDSI
CENTRE OF EXCELLENCE FOR DAIRY SKILLS IN INDIA

Advertisement for Empanelment of Subject Matter Experts (SMEs)

The Centre of Excellence for Dairy Skills in India (CEDSI) is an initiative taken by Agriculture Skill Council of India which aims to ensure sustainability and profitability in the dairy sector through skilling and capacity building, policy advocacy, knowledge management and research. Towards This CEDSI works with stakeholders across the dairy ecosystem including dairy farmers, wage workers, dairy cooperatives and corporates, research, academia, and central and state governments. It strives to be positioned as an innovator and leader in the dairy skilling space across the globe, who undertakes and facilitates applied manpower research in the dairy sector, capacity development in the areas of skilling and provides policy inputs at the national and state level to strengthen skill upgradation.

CEDSI invites applications for the empanelment of (SMEs) on various domains in Dairy, Agriculture and Allied Sectors.

Details mentioned below -

Pay and Allowances: As per CEDSI norms, on availing of the services

Last Date to apply: October 30th, 2021

Application Fee: Free

Master Training Program: The selected candidates may have to undergo a Master Trainer Program

Master Trainer Program Fee: INR 1000 (Virtual Training)

Eligible candidates can apply online through the link - https://bit.ly/cedsi_sme

List of domain sectors -

S. No.	Subject	Sector
1	Livestock Production and Management	**Animal Husbandry**
2	Animal Nutrition	
3	Animal Breeding & Reproduction	
4	Fodder Production and Preservation	
5	Milk Productivity Enhancement	
6	Animal Health, Disease Prevention	
7	Milk Quality Assurance	**Dairy Development**
8	Clean Milk Production	
9	Milk Procurement/Transportation/Chilling	
10	Sales & Marketing of Milk and Milk Products	
11	Organization and Management of Producer Institution	
12	Poultry Production	**Poultry**
13	Poultry Marketing and Processing	
14	Livestock GHG Emission and Mitigation	**Sustainable Dairying**
15	Water Management in Dairy Sector	
16	Waste Management	**Farm Management & Extension**
17	Farm Management/Farm Economics and Accounting	
18	Meat Processing, Preservation Storage and Marketing	**Meat Processing**
19	Value Addition in Meat & Egg Processing	

Candidate must have the following requisites -

- Complete knowledge of Vocational Education, Skill Development ecosystem and its stakeholders.
- Overall sectoral and industry knowledgeability to analyze/collate demand, prepare a sustainable plan/models of skill programs/courses/work-study model and skilling framework and field implementation of the planned activity
- Candidates must not be blacklisted by MSDE/NSDA/NSDC/SSC/UGC or any other institution where he has worked in the past
- For further queries (if any) please write us at **info@cedsi.in**

General Instructions for Applicants (applying for Subject Matter Expert) -

- The Candidate must be a citizen of India.
- Candidates will update their qualifications, experience and other credentials on the CEDSI website/application as and when there is any change.
- All qualifications and experiences will be considered as a cutoff date and, applications will be sent for scrutiny.
- The candidates are advised to satisfy themselves about their eligibility before applying for an SME for a job role in a particular sector. A valid (SMEs) Certificate/Experience Certificate is a must along with other conditions laid down for qualification and experiences in Industry/Sector.
- The prescribed essential qualifications and experience are minimum and mere possession of the same does not entitle a candidate to be enrolled.
- CEDSI may conduct an interview or assessment test if required. No TA/DA shall be paid to the candidates for attending the interview/ assessment test.
- Applications not accompanied with necessary/required documents, self-attested copies of degrees/certificates/experience certificates issued by the competent authority shall be rejected.
- Candidates must regularly visit CEDSI website (www.CEDSI.in) for all the details and updates related to further processes.
- In case of any inadvertent mistake in the process of recruitment/selection, if detected at any stage even after the issue of empanelment order, CEDSI reserves the right to modify/withdraw/cancel any communication sent to the candidates.
- The initial period of empanelment will be for 2 years and can be extended further on the basis of performance and criteria for enrollment.
- CEDSI will engage the expert for training/consultancy/involvement in project implementation and compensation will be given accordingly. Mere empanelment will not be subject to any compensation